3 छपारा में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत



5 पांच दशक की सियासत, सत्ता से शिखर तक



7 बच्चों को बेहतर भविष्य, बेहतर बचपन भी दीजिए



RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

# जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 26 प्रति सोमवार, 16 नवंबर 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

# छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षामंत्री गजेन्द्र यादव के इशारे पर हुआ लाखों स्कूली छात्राओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़

## क्या मुख्यमंत्री साय मंत्री गजेन्द्र यादव और सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह पर करेंगे कार्यवाही?



कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं के सरकार के कुछ मंत्री और अफसर साय सरकार की छवि को धूमिल करने में जुटे हुए हैं। दरअसल पिछले दिनों राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से जारी हुए एक टेंडर ने राज्य सरकार की कार्यशैली और उसकी मंशा पर सवालियां निशान लगा दिया है। आमजनता में चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है कि एक तरफ जहां सरकार बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ पर लगातार जोर दे रही है। वहीं, शासन का ध्यान बेटियों के स्वास्थ्य पर बिल्कुल नहीं है। सरकार बेटियों के स्वास्थ्य के मामले पर पूरी तरह से आंख में पट्टी और कान में ढिप्पी लगाकर बैठ गई है। शासकीय स्कूलों में छात्राओं को वितरित किये जाने वाले सैनेटरी नेपकिन की वितरण व्यवस्था पर स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग के आला अधिकारियों ने विभाग के मुखिया के कहने पर न सिर्फ सैनेटरी नेपकिन वितरण व निर्माण संबंधी कार्य पर अंकुश लगा दिया है बल्कि अपनी चहेती और पसंदीदा कंपनी को टेंडर जारी करने के लिए सभी सेवा शर्तें उसके अनुरूप तैयार कर दी है, जिससे टेंडर उसी कंपनी को मिल सके जिसे मंत्री देना चाहते हैं।




### 42 करोड़ के टेंडर पर लगी मंत्री जी की निगाहें

विभागीय सूत्रों के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगभग 42 करोड़ रुपये के टेंडर की प्रक्रिया का आदेश मुख्यमंत्री डॉ. विष्णुदेव साय ने पिछले दिनों एक बैठक में दिया था। विभाग के बाबू से लेकर अधिकारी तक सभी इस बड़े और मोटी राशि के टेंडर की प्रक्रिया में अपने-अपने हितों को साधने के हिसाब से जुट गये और आला अधिकारियों ने इस टेंडर प्रक्रिया के प्रस्ताव को पूरा तैयार कर लिया। जब विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस प्रस्ताव को लेकर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉ. कमलप्रीत सिंह के पास लेकर पहुंचे तो पूरी बाजी ही पलट गई। दरअसल कमलप्रीत सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री गजेन्द्र यादव के इशारे पर टेंडर की प्रक्रिया में शामिल की गई सभी शर्तों को बदल दिया और मंत्री गजेन्द्र यादव के अनुसार उसमें से स्व-सहायता समूह की महिलाओं को बाहर निकालने संबंधी शर्त डाल दी। आलम यह हुआ कि मंत्री और सचिव महोदय ने मिलकर वार्षिक आय 210 करोड़ रुपये कर दी जिससे स्व-सहायता समूह की महिलाएं इसमें दूर-दूर तक शामिल न हो सकें।

### छात्राओं के स्वास्थ्य से लापरवाही का जिम्मेदार कौन?

अब जब स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री गजेन्द्र यादव की भ्रष्टाचारी सोच और सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह की मंशा सामने आ गई तो उन्होंने जानबूझकर इस टेंडर को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मंत्री और सचिव की इस सांठगांठ ने एक बार फिर लाखों छात्राओं के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। (शेष पेज 2 पर)

# मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विजन युवा शक्ति को अवसर और आत्मनिर्भरता की राह

-विजया पाठक

रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप, आधुनिक तकनीक और शिक्षा के जरिए युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की पहल छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युवा शक्ति को प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य सामने रखा है। किसी भी राज्य का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी की शिक्षा, कौशल, रोजगार और उद्यमशीलता पर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध और जनजातीय बहुल राज्य में युवाओं की प्रतिभा को सही दिशा देना विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। मुख्यमंत्री साय की सरकार ने इसी सोच के साथ रोजगार, स्वरोजगार, तकनीकी शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, नवाचार और उद्यमिता को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प के अनुरूप मुख्यमंत्री साय विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर जोर दे रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का युवा केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर न रहे, बल्कि निजी क्षेत्र, उद्योग, कृषि आधारित उद्यम, स्टार्टअप और नई तकनीकों के माध्यम से भी अपने लिए अवसर तैयार करे।



### रोजगार के अवसरों का विस्तार

युवाओं की सबसे बड़ी अपेक्षा रोजगार है। इस दिशा में सरकार ने सरकारी भर्तियों के साथ निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री ने सितंबर 2026 में बताया कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में 700 से अधिक रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से लगभग 24 हजार युवाओं को रोजगार मिला। रायपुर में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेले में 95 से अधिक नियोक्ताओं ने भाग लिया और लगभग पांच हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बने। सरकार ने औद्योगिक विस्तार के माध्यम से कम से कम दो लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी सामने रखा है। इसके लिए उद्योगों में निवेश आकर्षित करने और स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों के मामले में भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की पहल भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न विभागों में 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी होने की जानकारी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दी। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। इसका उद्देश्य अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए निश्चित समय और स्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध कराना है। (शेष पेज 2 पर)

# मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विजन युवा शक्ति को अवसर और आत्मनिर्भरता की राह




(पेज 1 का शेष)

## कौशल विकास से उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयारी

आज रोजगार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। केवल डिग्री हासिल कर लेना नौकरी की गारंटी नहीं रह गया है। उद्योगों को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है, जिनके पास तकनीकी ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव और आधुनिक कौशल भी हो। मुख्यमंत्री साय ने इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। प्रदेश के 30 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की पहल की गई है। इसके साथ ही जिला स्तर पर संचालित आजीविका महाविद्यालयों के माध्यम से युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और अन्य आधुनिक तकनीकों से संबंधित पाठ्यक्रमों को आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों से जोड़ने की योजना भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है।

## 500 करोड़ का स्टार्टअप और निपुण मिशन

युवाओं को रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में सितंबर 2026 में स्वीकृत मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन एक महत्वपूर्ण पहल है। इस मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और पांच इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर विकसित करने की योजना है। इस मिशन का निपुण जॉब इंजन उद्योगों की मांग और युवाओं के कौशल के बीच सीधा तालमेल स्थापित करने में मदद करेगा। इससे युवाओं को केवल प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र तक सीमित रखने के बजाय वास्तविक रोजगार के लिए तैयार करने पर जोर रहेगा। तकनीकी प्रयोग, नवाचार और नए व्यावसायिक विचारों को प्रोत्साहन मिलने से प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को भी विस्तार मिल सकता है।

## स्टार्टअप से आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मानना है कि प्रदेश के युवाओं में प्रतिभा और नए विचारों की कमी नहीं है। जरूरत उन्हें उचित मंच, तकनीकी सहयोग, वित्तीय सहायता और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की है। सितंबर 2026 में आयोजित युवा नवाचार एवं उद्यमिता कॉन्क्लेव में उन्होंने युवाओं से नौकरी तलाशने के साथ-साथ स्वयं रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश में पांच हजार स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य रखा है। नए उद्यमियों को उनके नवाचार आधारित विचारों को व्यावसायिक स्वरूप देने के लिए 10 लाख रुपये तक की सीड फंड सहायता उपलब्ध कराने की पहल भी सामने रखी गई है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, तकनीक और स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन देने की संभावनाएं इस अभियान का हिस्सा हैं।

## आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भविष्य के लिए युवा तैयार

तकनीक के बदलते दौर में छत्तीसगढ़ के युवाओं को पीछे न रहना पड़े, इसके लिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में 500 करोड़ रुपये के एआई मिशन की पहल की गई है। इसके माध्यम से छह लाख विद्यार्थियों को एआई शिक्षा और प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त तकनीकी प्रयोगशालाओं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के विकास पर भी जोर है। एआई, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवाओं के लिए भविष्य में रोजगार और उद्यमिता के नए रास्ते खुल सकते हैं। मुख्यमंत्री का जोर इस बात पर है कि छत्तीसगढ़ का युवा केवल तकनीकी बदलाव का उपभोक्ता न बने, बल्कि नई तकनीक के विकास और उपयोग में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करे।

## सुशासन में युवाओं की भागीदारी

युवाओं की प्रतिभा का उपयोग केवल उद्योग और रोजगार तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अक्टूबर 2026 में इसके दूसरे बैच के 36 युवा फेलो के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद किया। इस कार्यक्रम में चयनित युवाओं को आईआईएम रायपुर में प्रशिक्षण और इसके बाद विभिन्न जिलों में प्रशासनिक कार्यों का व्यावहारिक अनुभव दिया जा रहा है। दो वर्षीय कार्यक्रम में पांच महीने का अकादमिक प्रशिक्षण और 19 महीने का मैदानी अनुभव शामिल है। इससे इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन, अर्थशास्त्र और अन्य विषयों के युवा शासन की वास्तविक चुनौतियों को समझ सकेंगे तथा नीतियों के क्रियान्वयन में अपने सुझाव दे सकेंगे।

## शिक्षा, छात्रवृत्ति और प्रतिभाओं को अवसर

युवाओं के भविष्य की नींव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से तैयार होती है। सरकार की ओर से सरकारी विद्यालयों में पाठ्यपुस्तक, गणवेश और मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के साथ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रयास आवासीय विद्यालयों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर दिया जा रहा है। दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जनजातीय युवाओं के लिए छात्रावास में निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति जैसी पहल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश पाने वाले पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के कारण प्रतिभाशाली युवाओं की उच्च शिक्षा में बाधा नहीं आने देना है।

## खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की पहल

युवाओं के सर्वांगीण विकास में खेलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। खेल प्रतिभाओं को पहचानने, उन्हें प्रशिक्षण देने और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के प्रारूप को 27 अक्टूबर 2026 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली। इसके लिए वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस मिशन में प्रतिभा पहचान से लेकर पदक प्राप्ति तक खिलाड़ियों के विकास की क्रमबद्ध व्यवस्था प्रस्तावित है।

# स्व-सहायता समूह की महिलाओं को बाहर कर निजी कंपनी को 42 करोड़ के टेंडर जारी करने की योजना

(पेज 1 का शेष)

सूत्रों के अनुसार निविदा टेण्डर शर्तों में सुरक्षा निधि से जुड़े शर्त में 180 दिन) की डिमाण्ड ड्राफ्ट की मांग की गई थी जबकि भारत में समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक 90 दिनों की अवधि के लिए चेक और डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करते हैं। यह भी बताया जाता है कि विपरीत 90 के बजाय 180 दिनों की मियाद अवधि की शर्त से कई कंपनियाँ टेण्डर निविदा से बाहर हो गई है। ऐसी स्थिति में वही कंपनियां सरकारी टेण्डर पाने में कामयाब होते नजर आ रही है जिनके लिए विशेष तौर पर टेण्डर की सेवा शर्तें निर्धारित की गई थी। आखिर छात्राओं के साथ बरती जा रही इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है।

## अधिकतर राज्यों में समूह की महिलाएं कर रही हैं निर्माण

मंत्री गजेन्द्र यादव और सचिव की जुगलबंदी ने जिस चालाकी से राज्य की स्व-सहायता समूह की महिलाओं को इस टेंडर की प्रक्रिया से बाहर निकाला है वह सोचने वाली बात है। क्योंकि मध्यप्रदेश सहित गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा कई ऐसे अन्य राज्य भी है जहां छात्राओं के लिए वितरित की जा रही सैनेटरी नेपकिन का निर्माण और वितरण व्यवस्था का कार्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्व-सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में यह पहली बार हुआ है कि स्व-सहायता समूह की महिलाओं को बाहर का रास्ता दिखाकर एक निजी कंपनी को बड़ा टेंडर जारी करने की तैयार की जा रही है। जबकि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक खुद भी स्व-सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं लेकिन साय मंत्रीमंडल के भ्रष्टाचारी मंत्री गजेन्द्र यादव साय सरकार की इमेज की मिट्टी पलीत करने में लगे हुए हैं।

## 450 करोड़ का पुराना माल खपाने की तैयारी

सूत्रों के अनुसार मंत्री गजेन्द्र यादव जिस कंपनी को टेंडर जारी करना चाहते हैं उसकी पहली शर्त यह है कि वह पहले पुराने और एक्सपायर सैनेटरी नेपकिन की डिलीवरी करेगी। जिसकी कीमत लगभग 450 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ऐसे में भ्रष्टाचारी गजेन्द्र यादव छात्राओं के स्वास्थ्य से लापरवाही करते हुए लगभग 100 करोड़ रुपये चट कर जाने की योजना पर काम कर रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी नाक के नीचे चल रहे भ्रष्टाचार के इस मायाजाल को तोड़ने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अगर उन्हें सही मायने में राज्य के भीतर सुशासन व्यवस्था लाना है और राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो आवश्यक है कि गजेन्द्र यादव और डॉ. कमलप्रीत सिंह जैसे भ्रष्टाचारी लोगों पर लगाम लगाएं। क्योंकि इससे न सिर्फ छात्राओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा बल्कि राज्य और मुख्यमंत्री साय की छवि पर भी प्रश्नचिन्ह लगेंगे।

# छपारा में काल बनी आग, एक ही परिवार के छह लोगों की दर्दनाक मौत

-अय्यूब कुरैशी

जगत प्रवाह. सिवनी। दीपावली की खुशियां सिवनी जिले के छपारा नगर में एक दर्दनाक हादसे के चलते मातम में बदल गईं। महावीर वार्ड स्थित जैन मोहल्ले में दीपावली की रात हुए भीषण अग्निकांड में एक ही परिवार के छह सदस्यों की जिंदा जलने के बजाय दम घुटने से मौत हो गई, जबकि चार लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस हृदयविदारक घटना से पूरे नगर में शोक की लहर फैल गई है। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले सभी छह सदस्यों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। 8 नवंबर की देर रात करीब 3:30 बजे सर्राफा एवं गिरवी व्यवसायी कुंदन लाल सोनी के तीन मंजिला मकान के निचले हिस्से में संचालित ज्वेलर्स दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह करीब 4 बजे आग की ऊंची लपटें दिखाई देने पर आसपास के रहवासियों ने बचाव एवं आग बुझाने के प्रयास शुरू किए।



सूचना मिलते ही छपारा पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। वहीं सिवनी एवं लखनादौन से दमकल वाहनों को बुलाया गया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सामने स्थित दुकान पर लगा फ्लेक्स करीब 12 फीट की दूरी पर होने के बावजूद पिघल गया। मकान की खिड़कियों में लगी लोहे की सरिया भी भीषण गर्मी के कारण टेढ़ी हो गईं। संकरी गलियों और आसपास बने सटे हुए मकानों के कारण राहत एवं बचाव कार्य में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हादसे के समय मकान में परिवार के कुल 10 सदस्य मौजूद थे। आग और धुएं के बीच पुलिस, दमकल कर्मियों एवं स्थानीय नागरिकों ने बचाव अभियान चलाया। इस दौरान मकान की दीवार तोड़कर चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन दुर्भाग्यवश परिवार के छह सदस्यों की जान नहीं बचाई जा सकी। हादसे की सूचना मिलते ही छिंदवाड़ा डीआईजी राकेश सिंह, सिवनी पुलिस अधीक्षक कृष्ण लाल चंदानी, कलेक्टर अंजू अरुण कुमार सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन एवं केवलारी विधायक रजनीश हरवंश सिंह ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं।

# कमलनाथ के जन्मदिन पर भोपाल में नकुलनाथ का शक्ति प्रदर्शन

## दीपावली मिलन समारोह में जुटे कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. भोपाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती और 18 नवंबर को मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित दीपावली मिलन समारोह के जरिए भोपाल में नकुलनाथ ने अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। समारोह को महज दीपावली मिलन तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे कांग्रेस के भीतर राजनीतिक सक्रियता और संगठनात्मक शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। कार्यक्रम में नकुलनाथ की मौजूदगी और आयोजन के राजनीतिक मायनों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस आयोजन के जरिए नकुलनाथ ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच अपनी सक्रियता का संदेश देने की कोशिश की। अब राजनीतिक गलियारों में सवाल है कि क्या यह आयोजन मध्यप्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ परिवार की राजनीतिक पकड़ और आगामी रणनीति का संकेत है?



# स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में काशीपुर और रुद्रपुर की उपलब्धि पर मुख्यमंत्री धामी ने दी बधाई

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में काशीपुर के महापौर दीपक बाली, रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा, शहरी विकास विभाग के निदेशक विनोद गोस्वामी, काशीपुर के नगर आयुक्त रवीन्द्र बिष्ट, रुद्रपुर की नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी तथा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के राज्य मिशन प्रबंधक मनोज पांडे ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत काशीपुर एवं रुद्रपुर को प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत उत्तराखण्ड के काशीपुर को प्रदेश में तथा रुद्रपुर को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान शहरी स्वच्छता, स्वच्छता प्रबंधन एवं शहरी स्थानीय निकायों में किए गए उल्लेखनीय सुधारों के लिए प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने इस उपलब्धि पर सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वच्छता कर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि काशीपुर और रुद्रपुर को प्राप्त यह सम्मान पूरे उत्तराखण्ड के लिए गौरव का विषय है। यह उपलब्धि स्वच्छता के प्रति जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और आम नागरिकों की सामूहिक प्रतिबद्धता, समर्पण एवं निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में संचालित स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता को जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है। उत्तराखण्ड में भी राज्य सरकार स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर शहरों के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

# गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं-बहनों और युवाओं का सर्वांगीण विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मुंगेली जिले में अधोसंरचना विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। लगभग 143 करोड़ रुपए की लागत के 25 सड़क विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। इन कार्यों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होगा तथा किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। अच्छी सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों का रास्ता भी खोलती हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों को बेहतर जल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इन कार्यों से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सिंचाई संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम होगी और उन्हें खरीफ के साथ रबी एवं अन्य फसलों की खेती के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इससे फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम है। कंतेली में महाविद्यालय भवन के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण अंचलों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

## किसानों की समृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध, 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसानों की मेहनत और समृद्धि से ही प्रदेश की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, कृषि लागत में राहत देने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर लगभग 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है।

# चीचली में मंत्री विश्वास सारंग और उदय प्रताप सिंह ने किए 12 शिलान्यास, स्थानीय नेताओं की उपेक्षा से आक्रोश

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। मंत्री विश्वास सारंग और मंत्री उदय प्रताप सिंह द्वारा चीचली में 12 विकास कार्यों के शिलान्यास किए गए। कार्यक्रम के बाद से स्थानीय नेताओं और संगठन के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। आरोप है कि शिलान्यास पट्टिकाओं में चीचली के स्थानीय नेताओं के नाम तक नहीं थे और संगठन को भी कोई महत्व नहीं दिया गया। स्थानीय नेताओं का कहना है कि दिन-रात संगठन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मंच पर भी स्थान नहीं मिला। कार्यक्रम में केवल चुनिंदा लोगों को ही तवज्जो दी गई, जबकि चिचली के स्थानीय नेता जो वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय हैं, उन्हें पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। जनता में भी इस बात को लेकर आक्रोश है। लोगों का कहना है कि मंत्री जी स्थानीय लोगों को हल्के में लेते हैं। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर स्थानीय नेता ही जनता के बीच रहते हैं, लेकिन जब श्रेय लेने की बारी आती है तो उन्हें भुला दिया जाता है। वहीं मंत्रियों के साथ रहने वाले कुछ लोग 24 घंटे उनकी आरती गाते हुए यह प्रचार कर रहे हैं कि अगली पंचवर्षीय में मंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो नेता अपने ही क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान नहीं कर सकता, वह प्रदेश का नेतृत्व कैसे करेगा? क्षेत्र में इस घटना के बाद से राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या विकास कार्यों का श्रेय केवल मंत्रियों को दिया जाएगा, या उन कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा जो जमीन पर काम करते हैं?

## सम्पादकीय

# महंगाई की मार से कराहता आम आदमी, कब मिलेगी राहत?

भारत में महंगाई अब केवल आर्थिक आंकड़ों और सरकारी रिपोर्टों तक सीमित विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन की सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। बाजार में सब्जियों से लेकर खाद्य तेल, दाल, दूध, रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल, दवाइयों और बच्चों की शिक्षा तक हर क्षेत्र में बढ़ते खर्च ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। स्थिति यह है कि महीने की शुरुआत में मिलने वाला वेतन महीने के अंत तक पहुंचते-पहुंचते जवाब देने लगता है। आमदनी सीमित है, लेकिन जरूरतों और खर्चों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आमजन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महंगाई की इस मार से राहत कब मिलेगी? महंगाई का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ता है, जिनकी आय का बड़ा हिस्सा खाने-पीने और रोजमर्रा की आवश्यकताओं पर खर्च होता है। निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए दाल, सब्जी, दूध और खाद्य तेल जैसी वस्तुओं की कीमतों में मामूली वृद्धि भी बड़ी परेशानी बन जाती है। वहीं मध्यम वर्ग के सामने बच्चों की स्कूल फीस, मकान का किराया, बिजली बिल, परिवहन, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने की चुनौती है। पहले जहां परिवार थोड़ी-बहुत बचत कर भविष्य की जरूरतों के लिए पैसा अलग रख पाते थे, वहीं अब बचत करना भी मुश्किल होता जा रहा है।

महंगाई की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बाजार में कीमतें बढ़ने के साथ आम आदमी की आय उसी अनुपात में नहीं बढ़ती। सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले अनेक कर्मचारियों के वेतन में सीमित वृद्धि होती है, जबकि रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार दबाव बनाती हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, छोटे दुकानदारों, रिक्शा चालकों और दिहाड़ी श्रमिकों की स्थिति तो और भी कठिन है। उनकी आमदनी अनिश्चित रहती है, लेकिन बाजार में वस्तुओं की कीमतें उनके लिए भी उतनी ही होती हैं जितनी किसी संपन्न व्यक्ति के लिए। यही आर्थिक असमानता महंगाई के प्रभाव को और गंभीर बनाती है। महंगाई के पीछे कई कारण होते हैं। कृषि उत्पादन में कमी, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां, परिवहन लागत में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति व्यवस्था की बाधाएं और जमाखोरी जैसे कारक वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करते हैं। कई बार मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन भी बाजार में कीमतें बढ़ा देता है। इसके अलावा ईंधन की कीमतों में वृद्धि का असर परिवहन से लेकर उत्पादन और वितरण तक दिखाई देता है। इसका अंतिम बोझ उपभोक्ता को ही उठाना पड़ता है।

यह भी चिंता का विषय है कि महंगाई केवल वर्तमान खर्चों को प्रभावित नहीं करती, बल्कि आम आदमी के भविष्य की योजनाओं पर भी असर डालती है। परिवार बच्चों की उच्च शिक्षा, मकान निर्माण, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए बचत करना चाहते हैं, लेकिन आवश्यक वस्तुओं पर बढ़ते खर्च के कारण उनकी योजनाएं पीछे छूट जाती हैं। कई परिवारों को अपनी जरूरतें सीमित करनी पड़ती हैं। कहीं पौष्टिक भोजन में कटौती होती है तो कहीं बच्चों की अतिरिक्त शिक्षा और मनोरंजन के खर्च कम करने पड़ते हैं। यह स्थिति किसी भी समाज की आर्थिक और सामाजिक सेहत के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती।

सरकार की जिम्मेदारी केवल महंगाई के आंकड़े प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि आमजन को राहत पहुंचाना भी है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर प्रभावी निगरानी, जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना तथा किसानों से लेकर उपभोक्ताओं तक आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाना जरूरी है। खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन, भंडारण और परिवहन की सुविधाओं में सुधार करना होगा। इसके साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने और आमजन की क्रय शक्ति मजबूत करने की दिशा में ठोस प्रयास जरूरी हैं।

## सियासी गहमागहमी

### कांग्रेस में पोस्टर से सियासी बवाल

मध्यप्रदेश कांग्रेस में अभी चुनावी रणभेरी बजने में वक्त है, लेकिन नेतृत्व को लेकर सियासी हलचल पोस्टरों के जरिए ही सामने आने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ के समर्थन में भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टरों ने पार्टी के भीतर नई चर्चा छेड़ दी है। पोस्टर पर लिखा नारा 'मध्यप्रदेश की मजबूरी है, नकुलनाथ जरूरी है' जितना चर्चा में है, उससे कहीं ज्यादा उन चेहरों की गैर मौजूदगी सुर्खियां बटोर रही है, जिन्हें प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में अहम माना जाता है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तस्वीरें पोस्टर से गायब हैं। सियासी सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह आगामी विधानसभा चुनाव पटवारी और उमंग सिंघार के नेतृत्व में लड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे में नकुलनाथ के समर्थन में लगे पोस्टर को नेतृत्व की दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने इसे एक छोटे कार्यकर्ता की गलती बताया है। लेकिन राजनीति में पोस्टर भी कई बार उन संदेशों को सार्वजनिक कर देते हैं, जिन्हें मंच से कहने में नेता संकोच करते हैं। सवाल यह है कि यह महज पोस्टर लगाने की चूक है या कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और प्रभाव की नई बहस का संकेत? फिलहाल तस्वीरों की इस सियासत ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

### मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें तेज

मध्यप्रदेश की सियासत में एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लेकर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें चर्चा में हैं। भाजपा के राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री बदलने की सुगबुगाहट को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इन चर्चाओं ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर समय-समय पर उठने वाली चर्चाओं के पीछे संगठनात्मक समीकरण, वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता और सरकार के कामकाज की समीक्षा जैसे कारणों को भी देखा जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री के बीच तालमेल को लेकर सामने आई खबरों ने भी इन अटकलों को हवा दी है। दूसरी ओर, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल जैसे अनुभवी नेताओं के नाम भी राजनीतिक चर्चाओं में आते रहे हैं। लेकिन भाजपा की राजनीति में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला केवल चर्चाओं या किसी नेता की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं होता। अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल की प्रक्रिया से ही तय होता है। फिलहाल डॉ. मोहन यादव को हटाने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

## हफ्ते का कार्टून




## ट्वीट-ट्वीट

प्रिय @crpfindia, आपके चेहरों ने सब कुछ कह दिया: आपने प्रधानमंत्री के झूठ पर यकीन नहीं किया।
उन्होंने हमें नपुंसक कहा। मेरी चुनौती बरकरार है। वो मुझसे बहस करें कि देशद्रोही कौन है और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन चल रहा है। कभी भी, कहीं भी।
मेरी गारंटी: बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं बचेगी।
-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi



आजादी की लड़ाई के समय सबसे ज्यादा जेल में रहने वाले कांग्रेसी, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, सामंती समाज को लोकतंत्र का ककहरा सिखाने वाले और कृषि प्रधान भारत को औद्योगीकरण की राह पर ले जाने वाले आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर शत-शत नमन।
-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath



## राजवीरों की बात

# कमलनाथ: पांच दशक की सियासत, सत्ता के शिखर से संघर्ष तक का सफर

**समता पाठक/जगत प्रवाह**



कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, नौ बार लोकसभा सांसद और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की राजनीतिक यात्रा अनुभव, संगठनात्मक कौशल, सत्ता, चुनौतियों और छिंदवाड़ा से उनके लंबे जुड़ाव की कहानी है। भारतीय राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जिनकी पहचान केवल किसी पद या राजनीतिक उपलब्धि से नहीं, बल्कि लंबे अनुभव, सत्ता के गलियारों में प्रभाव और संगठन के भीतर उनकी भूमिका से बनती है। कमलनाथ ऐसा ही एक नाम हैं। पांच दशक से अधिक समय तक कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे कमलनाथ ने राष्ट्रीय राजनीति से लेकर मध्यप्रदेश की सत्ता तक अपना अलग मुकाम बनाया। कभी केंद्र की राजनीति में प्रभावशाली मंत्री रहे, तो कभी मध्यप्रदेश कांग्रेस की कमान संभालकर पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। उनका राजनीतिक जीवन उतार-चढ़ाव, उपलब्धियों और चुनौतियों का लंबा दस्तावेज है। कमलनाथ का जन्म 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। उन्होंने कोलकाता के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज से वाणिज्य विषय में स्नातक (बीकॉम) की शिक्षा प्राप्त की। उनका विवाह अलका नाथ से हुआ। उनके दो पुत्र हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद उनका रुझान सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की ओर बढ़ा। युवा कांग्रेस के माध्यम से उन्होंने राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाई और धीरे-धीरे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के विश्वासपात्र नेताओं में स्थान बनाया।

कमलनाथ का राजनीतिक सफर ऐसे दौर में आगे बढ़ा, जब देश की राजनीति में इंदिरा गांधी का प्रभाव था। कांग्रेस संगठन में काम करते हुए उन्होंने अपनी पहचान एक कुशल रणनीतिकार और संगठनकर्ता के रूप में बनाई। वर्ष 1980 में उन्होंने मध्यप्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया। इसके बाद 1985, 1989 और 1991 में भी उन्होंने लगातार जीत दर्ज की। छिंदवाड़ा धीरे-धीरे उनकी राजनीतिक पहचान का पर्याय बन गया। 1991 में उन्हें केंद्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद 1995 में उन्होंने वस्त्र मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्य किया। इन जिम्मेदारियों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक अनुभव और नीतिगत समझ विकसित करने का अवसर दिया।

कमलनाथ का राजनीतिक कद वर्ष 2004 में और बढ़ा, जब केंद्र में यूपीए सरकार बनने के बाद उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। वैश्विक व्यापार, औद्योगिक विकास और निवेश से जुड़े विषयों पर उनकी सक्रियता रही। वर्ष 2009 में दोबारा लोकसभा पहुंचने के बाद उन्हें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। जनवरी 2011 में उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय संभाला। अक्टूबर 2012 से मई 2014 तक उनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी भी रही।केंद्र सरकार में लगातार महत्वपूर्ण मंत्रालयों का नेतृत्व करना उनके राजनीतिक अनुभव और कांग्रेस नेतृत्व में उनकी स्वीकार्यता को दर्शाता है। वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं में भी शामिल रहे। कमलनाथ की राजनीति का सबसे मजबूत आधार छिंदवाड़ा रहा है। वर्ष 1980 से 2014 तक वे नौ बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। यह उपलब्धि किसी भी नेता के लिए उल्लेखनीय है। उन्होंने इस क्षेत्र को केवल चुनावी राजनीति का केंद्र नहीं बनाया, बल्कि विकास और राजनीतिक संगठन के लिहाज से भी अपनी पहचान स्थापित की। सड़क, शिक्षा, औद्योगिक गतिविधियों और स्थानीय सुविधाओं के मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें क्षेत्र में एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। बाद में उनके पुत्र नकुलनाथ ने भी छिंदवाड़ा से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया।

मध्यप्रदेश की राजनीति में कमलनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि वर्ष 2018 में सामने आई। लंबे समय बाद कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को पीछे छोड़कर सरकार बनाई। 17 दिसंबर 2018 को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके सामने किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी, औद्योगिक निवेश, प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक चुनौतियों से निपटने की बड़ी जिम्मेदारी थी। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल लगभग 15 महीने का रहा। मार्च 2020 में कांग्रेस के भीतर राजनीतिक संकट गहराया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों के इस्तीफों के बाद सरकार अल्पमत में आ गई। विधानसभा में बहुमत साबित करने की स्थिति बनने से पहले ही 20 मार्च 2020 को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम ने मध्यप्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी कमलनाथ मध्यप्रदेश कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में संगठन को संभाला और विपक्ष की भूमिका निभाई। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में उनके नेतृत्व और संगठन की रणनीति को लेकर भी सवाल उठे। कमलनाथ की राजनीतिक यात्रा इस बात का उदाहरण है कि भारतीय राजनीति में लंबा अनुभव और मजबूत संगठनात्मक संबंध किसी नेता को दशकों तक प्रासंगिक बनाए रख सकते हैं। उनके खाते में केंद्रीय मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, नौ बार लोकसभा पहुंचने की उपलब्धि और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद का अनुभव दर्ज है। वहीं, राजनीतिक संकट, चुनावी पराजय और बदलते राजनीतिक समीकरण उनके सफर की चुनौतियां भी रहे हैं।

# EMCON 2026 में डॉ. आबिद ने हासिल किया प्रथम पुरस्कार, ग्वालियर का बढ़ाया मान

**-संतोष सिंह कुशवाह**



**जगत प्रवाह.** ग्वालियर। आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. आबिद ने अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस EMCON 2026 में प्रथम पुरस्कार हासिल कर ग्वालियर का नाम रोशन किया है। मुंबई में 30 अक्टूबर से 01 नवंबर तक आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश के चिकित्सा विशेषज्ञों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत आयोजित यंग फैकल्टी टॉक प्रतियोगिता में करीब 60 प्रतिभागियों के बीच डॉ. आबिद ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति से पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने बार-बार होने वाली गंभीर श्वसन विफलता से जुड़े एक जटिल क्रिटिकल केयर केस को प्रस्तुत किया। इसमें बीमारी के असामान्य कारण की पहचान और उपचार के महत्वपूर्ण चिकित्सकीय पहलुओं को विस्तार से बताया। उनकी क्लिनिकल समझ, सटीक निदान और केस की प्रभावी प्रस्तुति को निर्णायक मंडल ने सराहा। कॉन्फ्रेंस में लंदन, चीन, अमेरिका, यूएई और मलेशिया सहित विभिन्न देशों के विशेषज्ञों की भागीदारी रही। डॉ. आबिद की इस उपलब्धि से अस्पताल सहित ग्वालियर के चिकित्सा जगत में खुशी की लहर है।

# आभूषण दुकान में हुई 70 लाख रुपये की लूट, सात आरोपी गिरफ्तार









**-अमित राय**

**जगत प्रवाह.** हावड़ा। तीन अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने हावड़ा जिले के संकराइल थाना अंतर्गत डुइल्या झोरहाट स्थित एक आभूषण की दुकान में प्रवेश कर दुकान के मालिक को बंदूक की नोक पर धमकाया तथा उनके साथ मारपीट की। इसके पश्चात अपराधियों ने दुकान से सोने एवं चांदी के आभूषण लूट लिए, जिनका कुल अनुमानित मूल्य लगभग 70,00,000/- था। उक्त घटना के संबंध में संकराइल थाना ने मामले की विधिवत जांच प्रारंभ की गई। जांच के क्रम में संकलित तकनीकी सूचनाओं, भौतिक साक्ष्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण जांच संबंधी तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर इस लूटकांड में संलिप्त संदिग्ध आरोपियों की पहचान की गई। इसके उपरांत हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की एक विशेष टीम बिहार रवाना हुई तथा विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अरिंदम मजूमदार, नीरज कुमार कुशवाहा, अजीत पासवान, आशुतोष मिश्रा, नुरुल हक भास्कर सिंह और अभिषेक पांडेय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ एवं जांच के दौरान महत्वपूर्ण बरामदगी की गई। आरोपियों के कब्जे से लगभग 429 ग्राम सोने जैसे आभूषण तथा 4.2 किलोग्राम चांदी के आभूषण एवं अन्य वस्तुएं बरामद की गईं। इसके अतिरिक्त, एक 7 एमएम पिस्तौल भी बरामद की गई।

# अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध जिला प्रशासन की कार्यवाही

**-नरेन्द्र दीक्षित**

**जगत प्रवाह.** नर्मदापुरम। कलेक्टर आशीष वशिष्ठ के निर्देश पर जिले में रेत खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सिवनी मालवा तहसील में राजस्व, खनिज एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध कार्रवाई की गई। संयुक्त टीम द्वारा ग्राम पथाड़ा, बाबरी, डिमावर एवं भिलाड़िया में निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान रेत का अवैध उत्खनन करते हुए 6 मोटरबोट एवं एक पनडुब्बी जब्त की गई। जब्त किए गए सभी उपकरणों को पुलिस थाना शिवपुर की अभिरक्षा में रखा गया है। उक्त कार्रवाई में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी मालवा विजय राय, तहसीलदार नितिन झोड़, नायब तहसीलदार हीरू कुमरे, खनिज अधिकारी दिवेश मरकाम, सहायक खनि अधिकारी सूचि माथुर, खनि निरीक्षक बसंत पाटिल, खनिज सिपाही हेमंत राज सहित होमगार्ड एवं पुलिस बल के जवान उपस्थित रहे। जिला प्रशासन द्वारा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राजस्व, खनिज एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

# आंदोलन के बदलते स्वरूप



रघु ठाकुर
सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक और समाजवादी नेता

अक्टूबर माह देश के बड़े जनआंदोलनों के जनक नेताओं के स्मृति का माह माना जा सकता है। महात्मा गांधी ने तो समूचे देश को जाति, धर्म, धन और सभी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठाकर एकजुट किया और 19वीं सदी में दुनिया की तत्कालीन महाशक्ति ब्रिटिश साम्राज्य को उपनिवेशों की आजादी के लिये लाचार किया था। महात्मा गांधी का आजादी का आंदोलन भारत की आजादी का भी था और दुनिया के उपनिवेशों के मन में आजादी की भूख को पल्लवित कर उन्हें आजादी के संघर्ष के लिये प्रेरित करने वाला भी था। लगभग सारी दुनिया के उपनिवेशों के लोगों ने महात्मा गांधी में उनके अहिंसा के विज्ञान और तरीकों में आजादी को देखा और इसलिये महात्मा गांधी समूची दुनिया में आजादी और नैतिक जीवन मूल्यों के सबसे बड़े मान्य शाश्वत प्रतीक है। डॉ. लोहिया ने जून 1946 में ही गोवा मुक्ति संग्राम की शुरुआत की थी। आजादी के बाद समूचे देश के गरीबों और आम लोगों को अहिंसक सिविल नाफरमानी के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया, बल्कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह को आगे भी बढ़ाया और उस परंपरा को जीवित रखा। तत्कालीन कांग्रेस सरकार और उनके समर्थक बौद्धिकों की यह राय थी कि आजादी के बाद अब देश में सत्याग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु लोहिया ने इस विचार का जोरदार खंडन किया और लोगों को समझाया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया हुआ सबसे बड़ा हथियार अहिंसक सिविल नाफरमानी है जो न केवल व्यवस्था के अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देता है, बल्कि व्यक्ति को निर्भय भी बनाता और आजादी को भी बचाता है। लोहिया ने आजादी और समता के लक्ष्य को एक साथ जोड़ा तथा सात क्रांतियों के रूप में बांधा था। 1974 में जेपी ने भी बिहार के छात्र आंदोलन की अगुवाई स्वीकार करते हुये उसे संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के रूप में बदलने का प्रयास किया। उस दौर में शुरु हुये जनआंदोलन और राजनैतिक सत्ता आकांक्षाओं ने मिलकर इस आंदोलन में वैचारिक या राजनैतिक या अवसर की उम्मीद से सहभागिता की थी।

महात्मा गांधी के आजादी के आंदोलन और जेपी के आंदोलन में बड़ा फर्क था। गांधी का आंदोलन देश के जन-धन का आंदोलन था और जेपी का आंदोलन अराजनैतिक होने के उपदेश से शुरू होकर राजनैतिक दलों की सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा में बदल गया और अराजनैतिक से शुरू हुई यात्रा राजनैतिक दल के निर्माण यानि जनता पार्टी के निर्माण पर समाप्त हुई। इस आंदोलन का मौलिक रूप से कोई वैचारिक आधार नहीं था बल्कि यह एक गुजरात में महंगाई के मुद्दे से शुरू हुआ छात्र आंदोलन था जो बाद में वहां की सत्ता की दौड़ में पराजित राजनीति की सत्ता आकांक्षाओं का आंदोलन बन गया। जेपी के आंदोलन से भयभीत सरकार ने आपातकाल लगाया और फिर आपातकाल की मुक्ति के नाम पर एक ऐसा राजनैतिक दल उभरा जो विभिन्न प्रकार की परस्पर विरोधी विचारधाराओं का समूह था, तथा जो अपने जन्म से ही अपनी मृत्यु के लिये अभिसप्त था। इस आंदोलन और राजनैतिक दल की न कोई एक वैचारिक दृष्टि थी न ही कोई एक अंतरमन से स्वीकार्य नेतृत्व का केंद्र था। जनसंघ के मित्रों के लिये जेपी उतनी ही दूर तक स्वीकार थे जितनी दूर तक वे उनके आवरण में सत्ता हथिया सकते थे।

पिछले अप्रैल-मई के माह में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नीट पेपर लीक से पीड़ित छात्रों के लिये कटु और गैर जरूरी टिप्पणी जिसमें छात्रों को कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था कि प्रतिक्रिया भारत में कम हुई परंतु अमेरिका में अधिक हुई और अमेरिका में कॉकरोच जनता पार्टी बन गयी। बहुत लोगों की राय में यह स्वप्रेरित घटना नहीं थी बल्कि एक प्रायोजित प्रयोग था। पेपर लीक कांड और उसके बाद पुनरू परीक्षा तथा परीक्षा परिणाम आने के बाद व लगभग ग्यारह लाख पचास हजार छात्रों के पास होने के बाद एक युवा साथी अमेरिका से भारत आये। उन्हें भारत सरकार ने जंतर मंतर



दिल्ली में आंदोलन करने के लिये लाल कालीन बिछा दिया। पुलिस को बगैर किसी आवेदन और बगैर स्वीकृति के जंतर मंतर पर उनकी सभा हुई। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरे आदर सम्मान के साथ आंदोलन करने दिया और वे अगले जून माह की 20 तारीख को पुनरू आंदोलन की घोषणा कर अपने घर पूना चले गये। उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी गई थी, इसलिये उन्हें अपना घर छोड़कर अन्यत्र रहना पड़ रहा है। अब वे उन्हें लाकर अपने घर पर रखेंगे। महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने उनसे बैठक की, मुख्यमंत्री ने उनसे हालचाल जाना, परंतु किसी ने भी उनसे धमकी देने वाले का नाम और नंबर नहीं पूछा, क्योंकि इस पूछताछ से झूठ बेपर्दा हो सकता था। मीडिया ने भी उनके माता-पिता की धमकी की खबर जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी, परंतु किसी ने भी उनसे यह नहीं पूछा कि आखिर धमकी देने वाले कौन थे, ये घटनायें अपने आपसे काफी कुछ संकेत देती हैं? कारपोरेट और सत्ताधारी लॉबी उन्हें एक और केजरीवाल के रूप में खड़ा करना चाहती है। दुनिया के कारपोरेट से भारत के काफी स्वयंसेवी नाम के संगठन जीवन रस पाते हैं। उनमें दक्षिणपंथी भी हैं, वामपंथी भी हैं, कांग्रेसपंथी भी हैं और कुछ अन्य भी।

अमेरिका से भेजे गये छात्र नेता और उसके पीछे की रणनीति को ये वामपंथी संगठन भी बेहतर जानते हैं। जिनके लिये एक ही कुएं से पानी मिलता है, वे एक-दूसरे को बेहतर जानते हैं। प्रचार तंत्र के इस हमले के लाभ लेने के लिये वे भी सावधान थे तथा वामपंथी याने सीपीआई, सीपीएम, माले और एनजीओ के पुराने खिलाड़ी आम आदमी पार्टी के योद्धा देश के छितरे बितरे एनजीओ जो वर्षों से बेरोजगार थे, उन सभी को यहां संभावना नजर आई और वे सभी जंतर मंतर धरने में प्रवेश करा दिये गये। अन्ना हजारे का एक बार चेहरा चल चुका था, अतरू अब दूसरा सिक्का स्विटजरलैंड से सोनम वांगचुक को बुलाया गया।

खैर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 5-7 दिनों के खेल में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वह भाषा गांधी-लोहिया-जेपी के आंदोलन की भाषा नहीं थी। जेन-जी के नाम से जो नौजवान युवक युवतियों की टोली आई थी, उनके नारों में कुछ एक तो सुनने और कहने लायक भी नहीं है, वैसी आजादी की कल्पना कोई सभ्य समाज तो नहीं कर सकता, हो सकता है कि उनके परिवारजन और माता-पिता भी उसे स्वीकार न कर सकें?

आजादी के आंदोलन में नारे आजादी और गांधी तक सीमित थे, लोहिया के आंदोलन में नारे कार्यक्रमों और लोहिया के थे। जेपी के आंदोलन में नारे कुछ मुददों और जेपी तक थे। पर इस तथाकथित जेन जी के आंदोलन में नारे न कार्यक्रमों के थे, न नीतियों के थे, बल्कि अधिकांश तो गंदी गालियों के थे।

दूसरे इस आंदोलन में छात्रों और धरना देने वाले समूहों और पुलिस के बीच कटुता व टकराव था। तथा आंदोलन में गांधी के अनुशासन की मान्यतायें नहीं थी। लगभग हर व्यक्ति और समूह अपनी पहचान और रील बनाने के लिये नये-नये अपशब्दों और गालियों को गढ़ रहा था। संख्या की दृष्टि से यह बहुत छोटा आंदोलन था जिसमें अंतिम चरण में यानि जून के आखिरी समय में कुछ हजार लोग थे, वे किसी सूत्र में बंधे नहीं थे बल्कि वे अपने-अपने प्रतीक चिन्हों और राजनैतिक पहचान को स्थापित करने में लगे थे। जिसमें कुछ अमेरिका से प्रायोजित छात्र समूह, कांग्रेस समर्थक, आम आदमी पाटी, सपा के छात्र, एआईएसएफ और एआईएसए के वामपंथी, चन्द्रशेखर की भीम पार्टी कुछ अनुसूचित जाति के संगठन कुछ सवर्ण मानसिकता के आरक्षण विरोधी और यूजीसी नियमों को समाप्त करने की मांग करने वाले सब शामिल थे।

इस उन्मादी भीड़ ने न केवल पत्रकारों से बल्कि आंदोलन के समर्थक पत्रकारों से भी भारी अभद्रता की। एआई से बनाये गये चित्र और जुमले भी काफी चले ताकि देश में व छात्रों में एक उत्तेजना पैदा हो। अब दो दिनों से फिर जंतर मंतर पर एसआईआर के खिलाफ एक अभियान शुरू हुआ है, हालांकि यह अभियान आरंभ से ही विभाजित है। इसकी शुरुआत वामपंथी और आम आदमी पार्टी ने की और अब एक भिन्न तिथि पर कांग्रेस समर्थक समूह आयोजन कर रहे हैं, उसके बाद कॉकरोच समूह ने घोषणा की है कि अपनी-अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार राजनैतिक दल, सामाजिक समूह, विदेशी धन प्राप्त एनजीओ, तथाकथित सेलीब्रेटी हीरो-हीराइन इनमें शामिल होकर मीडिया में छप रहे हैं और अपनी फिल्मी भूमिका निभा रहे हैं। परंतु जो यह नई शैली आंदोलन की विकसित हो रही है वह और उसकी भाषा न गांधीवादी है, न लोहियावादी और न ही जेपी वाली। बल्कि एक अराजक समाज और नारीवाद के नाम पर पुरुष और नारी के बीच एक विभाजक रेखा खींचने का एक विकृत प्रयोग है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ऐसी घटनायें हुई हैं जिसने महिलाओं के मन में कुछ डर पैदा किया है। कांग्रेस के कार्यकाल में एक निर्भया कांड, ममता बनर्जी के काल में एक आर्जीकर की घटना हुई थी और भाजपा के काल में बंगाल, बिहार, मप्र में महिलाओं के नाम पर अनेकों घटनायें हुई हैं। अगर कोई ऐसा कानून बन सकता हो कि इन बेटियों के खिलाफ जुर्म करने वालों को तत्काल मृत्युदंड दिया जा सकता हो तो उसे बनाया जाना चाहिये। परंतु हर पुरुष अपराधी है, यह कहना उचित नहीं है? क्या कुछ महिलाओं के द्वारा अपने पतियों की हत्या के लिये सारी महिलायें अपराधी हैं? मेरी राय में ये दोनों दृष्टिकोण गलत होंगे। जो समाज में, परिवारों में और घरों में मानसिक विभाजन रेखा खीचेंगे और संशय पैदा करेंगे। परिवार की टूटती संस्था पर एक और चोट करेंगे। कुछ बेटियों ने नारा लगाया कि एक कचौड़ी दो समोसा, मर्द जात का क्या भरोसा? क्या उन्हें अपने पिता, भाई पर से विश्वास टूट चुका है? अगर ऐसा है तो यह सोच देश को नष्ट करने वाली होगी।

मीडिया और सोशल मीडिया में कुछ पुलिस के खिलाफ तथा महिला विरोधी व्यवहार के चित्र आये हैं, उनकी जांच और पुष्टि अभी होना है। पिछले जून माह में ऐसी कुछ घटनायें रील के माध्यम से प्रचारित की गई थी, परंतु उनकी भी कोई सत्यता प्रमाणित नहीं हुई। अब यह झूठ प्रचार तथाकथित जेन जी आंदोलन के लिये मुद्दा भी नहीं बचा।

अगर किसी पुलिस अधिकारी ने किसी बेटी के साथ आपराधिक कृत्य किया है तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिये परंतु यह भी आश्चर्यजनक है कि सैकड़ों महिला पुलिस तथा सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की उपस्थिति में ऐसी घटना हो और लोग रील बनाये, परंतु उसका प्रतिकार न करें? क्या महिला पुलिस में एक भी ऐसी महिला नहीं थी? क्या आंदोलनकारियों में क्या कोई भी आंदोलनकारी नहीं था जो पुलिस अधिकारी से टकरा सकता था? जिसे उस बेटी में अपनी बेटी नजर आई हो। यह चिंता का विषय है। समूचे समाज को अब और राजनैतिक दलों को आंदोलन की नैतिकता और भाषा की सीमायें बांधना चाहिये तथा पुलिस को भी अपनी मानवीय मर्यादायें सीमांकित करनी चाहिये। भूलना नहीं है कि हम सैकड़ों साल विदेशी गुलामी में रहे हैं। क्योंकि हम जातियों में बंटे हुए थे। अब अगर पुरुष और नारी के भेद में इस प्रकार बंट जायेंगे तो क्या देश के सारे राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पीछे नहीं छूट जायेंगे? तब परिवार में आपसी विश्वास नहीं होगा। तो क्या देश वास्तव में एक देश रह पायेगा?

हमें आज बहन सौफिया कुरैशी को आदर्श मानना होगा, वह धर्म, जाति से ऊपर उठकर अपने देश की सुरक्षा के लिये समर्पित और आदर्श हैं। उस भारतीय मूल की बेटी सुनीता विलियम्स को आदर्श मानना होगा, जो आठ माह तक नासा अमेरिकी अंतरिक्ष में एक पुरुष सहकर्मी के साथ रही और दोनों ने अपने राष्ट्रीय लक्ष्य के लिये अपने जीवन को दांव पर लगाया और नैतिक मूल्यों की सीमा रेखा को नहीं तोड़ा। हालांकि यह अमेरिकी समाज का प्रशंसनीय पक्ष है। ऐसे ही उदाहरणों से राष्ट्रीय एकता और देश मजबूत होता है। अगर हर नारी यह मानने लगे कि हर पुरुष अपराधी है तो इसका एक अर्थ यह भी है कि नारी को अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। नारी को अपना आत्मविश्वास तथा साहस, बचाना होगा। नर-नारी की समानता, एक आदर्श लक्ष्य है, जिसमें कोई पक्ष न कमजोर होता है, न पूर्णतरू बुरा। अगर द्रोपती के चीरहरण के लिये, एक पुरुष दुर्योधन अपराधी था तो उसके सम्मान की रक्षा करने वाला एक और पुरुष कृष्ण भी तो था।

# बच्चों को बेहतर भविष्य ही नहीं, बेहतर बचपन भी दीजिए

**आज की बात**



प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

आज का बच्चा पहले से अधिक जानकार है, लेकिन क्या उतना ही खुश भी है? उसकी उँगलियों पर पूरी दुनिया की जानकारी है, लेकिन क्या उसके पास अपनी बात कहने वाला कोई है? वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवाल पूछ सकता है, लेकिन अपने माता-पिता से हर सवाल पूछने में कितना सहज है? हम बच्चों को स्मार्ट बनाने की होड़ में कहीं उनका बचपन तो नहीं छीन रहे? महंगे स्कूल, कोचिंग, गैजेट्स और सुविधाओं को बेहतर परवरिश का पैमाना मान लिया गया है। बच्चों की दिनचर्या उपलब्धियों और अपेक्षाओं से भर रही है, जबकि खेल, दोस्ती और छोटी-छोटी खुशियों के लिए समय सिमट रहा है। बाल दिवस पर हमें सोचना होगा कि हम अगली पीढ़ी को केवल सफल बनाना चाहते हैं या संवेदनशील, आत्मविश्वासी और खुशहाल इंसान भी?

### बदलती पीढ़ी, बदलती सोच

जेन Z के अनेक युवा अब वयस्क हो चुके हैं, जबकि जेन अल्फा का बचपन डिजिटल दुनिया के बीच आकार ले रहा है। ये पीढ़ियाँ नए विचारों, तकनीक और वैश्विक अवसरों से परिचित हैं। इनमें स्वतंत्र सोच, जिज्ञासा और बदलाव स्वीकारने की क्षमता है। लेकिन तेजी से बदलती दुनिया इनके सामने पहचान, भविष्य और अपेक्षाओं की नई चुनौतियाँ भी रखती है। इनके सवालों को बदतमीजी और असहमति को अवज्ञा समझना बंद कीजिए। हर नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के अनुभव चाहिए, लेकिन अपनी सोच विकसित करने की स्वतंत्रता भी।

### तकनीक साधन बने, सहारा नहीं

इंटरनेट और एआई ने सीखने, रचनात्मकता और नई खोजों के असाधारण अवसर दिए हैं। लेकिन तैयार उत्तरों पर बढ़ती निर्भरता बच्चों की मौलिक सोच कमजोर कर सकती है। सोशल मीडिया की बनावटी चमक, ऑनलाइन तुलना, साइबर बुलिंग और स्क्रीन की लत भी गंभीर चुनौतियाँ हैं। बच्चों को तकनीक से दूर रखना समाधान नहीं। उन्हें जानकारी की सत्यता परखना, डिजिटल सुरक्षा समझना और स्क्रीन के बाहर की दुनिया से जुड़ना सिखाइए। मशीन से उत्तर लेना आसान है, लेकिन सही सवाल पूछना और स्वतंत्र निर्णय लेना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है।

### अंकों से व्यक्तित्व मत आँकिए

प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन बचपन को लगातार परीक्षा बनाना उचित



**14 नवंबर बाल दिवस पर विशेष**

नहीं। हर बच्चा टॉपर नहीं होगा और हर प्रतिभा मार्कशीट में दिखाई भी नहीं देती। कोई अच्छा खिलाड़ी है, कोई कलाकार, कोई नेतृत्व में कुशल तो कोई नई समस्याओं का समाधान खोज सकता है। बच्चों की तुलना उनकी क्षमताओं को निखारने के बजाय आत्मविश्वास कमजोर कर सकती है। असफलता पर ताने नहीं, दोबारा प्रयास करने का साहस दीजिए। शिक्षा केवल नौकरी पाने की तैयारी नहीं, जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी विकसित करे।

### सुविधाओं से ज्यादा साथ दीजिए

आज कई घरों में बच्चों के लिए अलग कमरे, महंगे खिलौने और आधुनिक सुविधाएँ हैं, लेकिन साथ बैठकर बातचीत करने का समय कम है। माता-पिता की व्यस्तता समझी जा सकती है, पर बच्चों को केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं, भावनात्मक उपस्थिति भी चाहिए। उनकी छोटी उपलब्धियों की सराहना कीजिए, परेशानियों को गंभीरता से सुनिए और बिना टोके अपनी बात कहने दीजिए। याद रखिए, बच्चे उस घर में सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, जहाँ गलती स्वीकार करने पर अपमान का डर नहीं होता।

### हर मुस्कान खुशी नहीं होती

अच्छे अंक, सामान्य व्यवहार और हँसता चेहरा हमेशा मानसिक संतुलन की गारंटी नहीं हैं। चिंता, अकेलापन, असुरक्षा और साथियों का दबाव बच्चों को भीतर से परेशान कर सकते हैं। अचानक चुप्पी, व्यवहार में बदलाव या लगातार उदासी को केवल उम्र का असर मानकर टालना उचित नहीं। स्कूलों में भावनात्मक शिक्षा और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को समझाइए कि मदद माँगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। भावनाओं को दबाने से नहीं, समझने से व्यक्तित्व मजबूत बनता है।

### दो बचपन, एक ही देश

एक तरफ बच्चे एआई से पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ अनेक बच्चों के पास किताबें, पर्याप्त पोषण और सुरक्षित वातावरण तक नहीं है। बाल श्रम, बाल विवाह और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में असमानता आज भी गंभीर चुनौतियाँ हैं। सरकार, विद्यालय और समाज की जिम्मेदारी केवल योजनाएँ बनाने तक सीमित नहीं रह सकती। हर बच्चे तक अवसर पहुँचाना जरूरी है। किसी देश की प्रगति केवल प्रतिभाशाली बच्चों की सफलताओं से नहीं, बल्कि सबसे वंचित बच्चे को मिले अवसरों से भी मापी जानी चाहिए।

### संस्कार सिखाइए नहीं, जीकर दिखाइए

बच्चे उपदेशों से अधिक हमारे आचरण से सीखते हैं। हम ईमानदारी की बात करें और स्वयं नियम तोड़ें, तो सीख खोखली हो जाती है। घर में महिलाओं का सम्मान, बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता, घरेलू कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी बच्चों के सामने उदाहरण बनें। उन्हें केवल आज्ञाकारी नहीं, विवेकशील बनाइए। अच्छे संस्कारों का अर्थ हर बात मान लेना नहीं, सही और गलत में अंतर समझकर सही का साथ देना है।

### बाल दिवस का वास्तविक संकल्प

भारत में 14 नवंबर को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है। बच्चों के प्रति उनके स्नेह से जुड़ा यह अवसर आज हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है।

भविष्य की दुनिया नई तकनीकों और बदलते अवसरों से भरी होगी। हमें बच्चों को उसके लिए तैयार करना है, लेकिन उनका वर्तमान खोकर नहीं। उन्हें खेलने, गलतियाँ करने, सवाल पूछने और अपने सपने चुनने का अवसर दीजिए। बच्चे हमारे अधूरे सपने पूरे करने का माध्यम नहीं, अपने सपने जीने वाले स्वतंत्र व्यक्तित्व हैं। बाल दिवस पर केवल यह मत सोचिए कि हम बच्चों के लिए कैसी दुनिया छोड़ेंगे, यह भी सोचिए कि हम दुनिया के लिए कैसे बच्चे तैयार कर रहे हैं। क्योंकि बचपन केवल भविष्य की तैयारी नहीं, जीवन का वह अनमोल समय है, जिसे दोबारा नहीं जिया जा सकता।

बच्चों को ऊँची ऊड़ान का आसमान दीजिए,
लेकिन उनके बचपन को भी मुस्कुराने दीजिए।

# छठः एक ही सूरज की संतान, एक ही जल में समर्पण

**पर्यावरण की फिक्र**



डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

भारत के अनेक पर्वों में छठ महापर्व केवल एक त्योहार नहीं, जन-जीवन की आत्मा है। यह बिहार और पूर्वांचल की मिट्टी से उठकर पूरे देश के हृदय में आस्था, समरसता और सांस्कृतिक एकता का संदेश फैलाता है। जहाँ जल है, वहीं छठ का घाट है; जहाँ सूरज है, वहीं लाखों हृदयों की एक साझी प्रार्थना है। छठ सूर्य की आराधना का पर्व है, पर इसका गहरा अर्थ मानवता की साधना है। जल में खड़े होकर दिया गया अर्घ्य केवल पूजा नहीं, समाज की असमानताओं को मिटाने का एक जीवंत संकल्प है। घाट पर सब एक साथ खड़े होते हैं। कोई ऊँचा नहीं, कोई नीचा नहीं; सब एक ही सूर्य के सामने समान हैं। सूर्य वह देवता हैं जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, और शायद इसलिए छठ हमें बराबरी का सच्चा अर्थ सिखाता है। सूर्य की किरणें किसी महल या झोपड़ी में भेद नहीं करतीं- वह हर चेहरे पर समान उजाला बिखेरती हैं।

जब उदयाचल पर सूर्य झुकता है और लाखों दीप उसके साथ एकाकार हो जाते हैं, तब यह पर्व बताता है- सच्चा धर्म ग्रंथों में नहीं, मानवता में है। छठ हमें याद दिलाता है कि प्रकृति किसी भेद को नहीं मानती, वह सबको एक साथ जीवन देती है। यही कारण है कि हर घाट, हर गीत, हर परंपरा कहती है- "हम सब उसी एक सूरज की संतान हैं, जो किसी को अलग नहीं देखता।" छठ का सबसे सुंदर दृश्य है- घाट पर उतरती भीड़। गाँव से लेकर शहर तक, अमीर से गरीब तक, सब एक ही जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यहाँ कोई ऊँच-नीच नहीं, कोई विशेषाधिकार नहीं- बस समानता, समरसता और साझा आस्था का संगम। यही छठ की आत्मा है- लोक का लोकतंत्र, जहाँ सबको बराबर सूर्य, बराबर सम्मान और बराबर स्थान मिलता है।

इसके केंद्र में है स्त्री। परवैतिन, जो संयम, तपस्या और श्रद्धा का जीवंत प्रतीक बनकर सबके कल्याण की कामना करती है। उसकी प्रार्थना सीमाओं से परे होती है अपने के लिए भी, पराए के लिए भी। इसी से वह पूजा की पात्रा नहीं, बल्कि संस्कृति की संरक्षिका बन जाती है। छठ का घाट बताता है कि सच्ची आस्था वही है जो भेद मिटाती है। जब जल में सूर्य की किरणें प्रतिबिंबित होती हैं, तो लगता है हर हृदय में वही प्रकाश जल रहा है। यही क्षण धर्म को कर्मकांड से उठाकर समानता और मानवता के उत्सव में बदल देता है। छठ केवल पूजा नहीं, समाज का आत्मबोध है। यह हमें याद दिलाता है कि राजनीति नहीं, लोक-आस्था ही समाज की असली शक्ति है; और हर बार जब लोग गाँव लौटते हैं, तो वे अपने मूल, अपनी मिट्टी, अपनी अस्मिता की ओर लौटते हैं। छठ का सबसे सुंदर दृश्य है घाट पर उतरती भीड़। एक ही जल में अमीर-गरीब, ऊँच-नीच, सब समान होकर खड़े होते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं। यह लोक का सच्चा लोकतंत्र है, जहाँ सबको बराबर सूर्य, बराबर सम्मान मिलता है।

इस पर्व के केंद्र में है स्त्री परवैतिन, जो अपने व्रत से केवल परिवार नहीं, पूरे समाज का कल्याण माँगती है। उसका संयम और श्रद्धा छठ को आस्था से आगे बढ़ाकर संस्कृति और समरसता का उत्सव बना देती है।

अर्घ्य के क्षण में जब सूर्य की किरणें जल में चमकती हैं, तो लगता है जैसे हर हृदय में वही एक प्रकाश जल उठा हो। यही क्षण धर्म को कर्मकांड से उठाकर समानता के उत्सव में बदल देता है। छठ का घाट किसी सभा जैसा है जहाँ कोई नेता नहीं, केवल सहभागी हैं; कोई भाषण नहीं, केवल गीत हैं। यही बताता है कि समाज की असली शक्ति राजनीति नहीं, लोक-आस्था में है। जब लोग अपने गाँव लौटते हैं, तो वे सिर्फ पूजा करने नहीं, अपनी जड़ों से मिलने आते हैं। इस लौटने में आस्था भी है, आत्मा भी , और एक ऐसी एकता की झलक, जो पूरे समाज को प्रकाशमान कर देती है। घाट पर उतरते ही सबकी पहचान मिट जाती है , न कोई ऊँचा, न नीचा, सब एक ही जल, एक ही सूर्य, एक ही भाव में समर्पित। छठ सिखाता है कि आस्था ही सबसे बड़ा समतुल्यक है जो समाज को बराबरी का पाठ पढ़ाती है। अर्घ्य के क्षण में जब सूर्य की किरणें जल में उतरती हैं, तो लगता है हर हृदय में वही एक प्रकाश जल रहा है जहाँ धर्म कर्मकांड नहीं, बल्कि मानवता और समानता का उत्सव बन जाता है। जब सूर्य की किरणें जल में उतरती हैं, तो प्रतीत होता है कि हर हृदय में वही प्रकाश जल उठा है। तब छठ केवल पूजा नहीं रहता— वह मानवता, समानता और समरसता का महापर्व बन जाता है। यही है छठ की सबसे बड़ी शिक्षाः "हम सब उसी एक सूरज की संतान हैं, जो किसी को अलग नहीं देखता।"

# सुशासन के संकल्प से

## नवा रायपुर बन रहा

# एजुकेशन हब

प्रबंधन | उद्यमिता | नवाचार

**NSTI**
नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट

**NIELIT**
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी

**NMIMS**
नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज

**NIFT**
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी



**NFSU**
नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी कैम्पस

R.O. No. : 14133/ 1






श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

/ChhattisgarhCMO | /DPRChhattisgarh | www.dprcg.gov.in

सुशासन से समृद्धि की ओर


स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
**RNI-MPBIL/2011/39805** समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)